भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3477

उत्तर देने की तारीख 10 अगस्त, 2026

सोमवार, 19 श्रावण, 1948 (शक)

देवरिया में कौशल विकास केंद्र

†3477.श्री शशांक मणि:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) और प्रशिक्षुता कार्यक्रमों के अंतर्गत देवरिया जिले में कार्यशील कौशल विकास केंद्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान नामांकित, प्रशिक्षित, प्रमाणित और नियोजित उम्मीदवारों की राज्य-वार और लिंग-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) राज्य-वार औसत प्लेसमेंट वेतन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देवरिया में कौशल की अवसंरचना को मजबूत करने तथा स्थानीय रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न स्कीमों, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन स्कीम (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया जिला सहित देशभर में समाज के सभी वर्गों को कौशलीकरण, पुनर्कौशलीकरण एवं कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौशल भारत मिशन का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशलों से सुसज्जित करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की योजनाएँ मांग-आधारित हैं तथा इन योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना अथवा उन्हें संबद्ध किया जाना आवश्यकता

के आधार पर, उद्योग भागीदारों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ समन्वय करते हुए किया जाता है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत देवरिया जिले में संचालित कौशल विकास केंद्रों की संख्या निम्नानुसार है:

स्कीम का नाम	**प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या**
पीएमकेवीवाई (एसटीटी+एसपी)	30
एनएपीएस	81
जेएसएस	01
पीएमकेके	02
सीटीएस/ आईटीआई	71

(ख) और (ग): कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की योजनाओं में से, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत योजना के प्रथम तीन चरणों अर्थात् पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0, जिन्हें वित्तीय-वर्ष 2015-16 से वित्तीय-वर्ष 2021-22 तक कार्यान्वित किया गया, में अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक के अंतर्गत नियोजन का विवरण दर्ज किया जाता था। इन चरणों के अंतर्गत अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) में 56 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को प्रमाणित किया गया, जिनमें से 24.38 लाख अभ्यर्थियों के योजना के अल्पावधि प्रशिक्षण घटक के अंतर्गत नियोजित होने की सूचना प्राप्त हुई। इसके अलावा, पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुसार विविध आजीविका एवं करियर विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाने पर विशेष बल दिया गया है तथा उन्हें इसके अनुरूप आवश्यक मार्गदर्शन एवं अभिमुखीकरण प्रदान किया जाता है। अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान द्वारा किए गए स्वतंत्र तृतीय-पक्ष मूल्यांकन से यह संकेत मिलता है कि मंत्रालय की प्रमुख कौशल विकास स्कीमों के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की आजीविका से होने वाली आय में वृद्धि हुई है तथा प्रशिक्षण के पश्चात उनकी आय में सुधार दर्ज किया गया है।

पिछले पाँच वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान नामांकित, प्रशिक्षित एवं प्रमाणित अभ्यर्थियों की राज्यवार तथा जेंडर-वार कुल संख्या का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ): देश में देवरिया जिला सहित कौशल अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा स्थानीय रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना एक व्यापक नियामक निकाय के रूप में की गई है जो तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियम और मानक स्थापित करती है।
ii. एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग बॉडीज से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग की मांग के अनुसार योग्यताएं विकसित करें और उन्हें राष्ट्रीय व्यवसाय

वर्गीकरण, 2015 के अनुसार पहचाने गए व्यवसायों के साथ मैप करें और उद्योग से मान्यता प्राप्त करें।

iii. संबंधित क्षेत्रों के उद्योग जगत के अग्रणियों के नेतृत्व में 36 क्षेत्रीय कौशल परिषदें (एसएससी) स्थापित की गई हैं, जो संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल दक्षता मानकों को निर्धारित करती हैं।

iv. एमएसडीई के तत्वावधान में प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) फ्लेक्सी एमओयू योजना और दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (डीएसटी) को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य आईटीआई के छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करना है।

v. पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, नई नवयुगीन/भविष्य के कौशल से संबंधित जॉब रोल्स को एआई/एमएल, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, ड्रोन प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में, आगामी बाजार मांग और उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से उद्योग 4.0 की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है,

vi. डीजीटी ने सीटीएस के तहत नवयुगीन/भविष्य के कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए हैं ताकि 5जी नेटवर्क तकनीशियन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग सहायक, साइबर सुरक्षा सहायक, ड्रोन तकनीशियन आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

vii. राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर संस्थानों के लिए उद्योग से जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए डीजीटी ने आईबीएम, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, एडब्ल्यूएस आदि जैसी आईटी प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारियां आधुनिक प्रौद्योगिकियों तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायक हैं।

viii. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा के साथ अधिक एकीकृत करने और अकादमिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के बीच सुगम आवागमन को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है। इसी दृष्टिकोण के अनुरूप, यूजीसी और एआईसीटीई के सहयोग से विकसित शिक्षुता-आधारित डिग्री कार्यक्रम (एईडीपी) डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों को उनके पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह कार्यक्रम रोजगार क्षमता को बढ़ाता है, परिणाम-आधारित अधिगम को बढ़ावा देता है, उद्योग-अकादमिक संबंधों को सुदृढ़ करता है और उद्योग-संबंधी कौशल प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है।

ix. एमएसडीई ने स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) शुरू किया है, जो एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है और कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता इकोसिस्टम को आपस में जोड़कर हितधारकों के व्यापक समूह को लक्षित करते हुए जीवनभर चलने वाली सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करता है। प्रशिक्षित उम्मीदवारों का ब्यौरा संभावित नियोक्ताओं से जुड़ने के लिए सिद्ध पोर्टल पर उपलब्ध है। स्किल इंडिया डिजिटल हब के माध्यम से, उम्मीदवार रोजगार और शिक्षुता के अवसरों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं।

x. कौशल महोत्सव और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले (पीएमएनएएम) का आयोजन प्रमाणित उम्मीदवारों को रोजगार और शिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए किया जाता है।

xi. सरकार ने 60,000 करोड़ रुपये के निवेश से पीएम-सेतु (उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास और रोजगार क्षमता परिवर्तन) नामक एक केंद्रीय प्रायोजित योजना शुरू की है। इस योजना अंतर्गत देश भर में 1,000 सरकारी आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा, जिसमें 200 हब आईटीआई और 800 स्पोक आईटीआई शामिल होंगे। पीएम-सेतु का मुख्य उद्देश्य उद्योग-आधारित शासन के माध्यम से रोजगार क्षमता में सुधार करना है, और यह अप्रत्यक्ष रूप से स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देता है। इसके तहत शिक्षार्थियों (शुरुआती चरण के उद्यमों और पहली बार उद्यम करने वालों सहित) को उद्योग से संबंधित कौशल प्राप्त करने, वास्तविक कार्य वातावरण का अनुभव प्राप्त करने और सुदृढ़ संस्थागत प्रणालियों और उद्योग संबंधों के माध्यम से कैरियर मार्गदर्शन, प्लेसमेंट सहायता और स्वरोजगार सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाता है।

अनुबंध

'देवरिया में कौशल विकास केंद्र' के संबंध में दिनांक 10.08.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3477 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले पाँच वर्षों और चालू वर्ष (दिनांक 30.06.2026 तक) के दौरान नामांकित, प्रशिक्षित और प्रमाणित उम्मीदवारों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, जेंडर-वार ब्यौरा।

(i) एनएपीएस:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नामांकित			प्रशिक्षित			प्रमाणित		
	पुरूष	महिला	ट्रांसजेंडर	पुरूष	महिला	ट्रांसजेंडर	पुरूष	महिला	ट्रांसजेंडर
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	393	173	0	393	173	0	143	45	0
आंध्र प्रदेश	84,711	23,884	0	84,711	23,884	0	21,482	1,762	0
अरुणाचल प्रदेश	222	221	0	222	221	0	45	26	0
असम	29,208	19,856	0	29,208	19,856	0	7,415	1,455	0
बिहार	27,467	6,933	0	27,467	6,933	0	5,661	665	0
चंडीगढ़	4,260	2,127	0	4,260	2,127	0	966	267	0
छत्तीसगढ	21,195	4,736	0	21,195	4,736	0	13,009	1,882	0
दिल्ली	83,599	27,155	1	83,599	27,155	1	7,073	1,821	0
गोवा	31,012	15,134	0	31,012	15,134	0	2,587	1,478	0
गुजरात	3,66,014	88,344	0	3,66,014	88,344	0	98,185	8,048	0
हरियाणा	2,82,763	64,809	1	2,82,763	64,809	1	74,160	17,237	3
हिमाचल प्रदेश	36,017	9,115	0	36,017	9,115	0	4,629	559	0
जम्मू और कश्मीर	4,106	1,031	0	4,106	1,031	0	862	148	0
झारखंड	45,378	6,690	0	45,378	6,690	0	22,600	1,461	0
कर्नाटक	3,14,591	99,575	2	3,14,591	99,575	2	49,685	7,429	0
केरल	48,076	19,918	1	48,076	19,918	1	21,930	7,549	0
लद्दाख	79	119	0	79	119	0	43	44	0
लक्षद्वीप	19	22	0	19	22	0	30	14	0
मध्य प्रदेश	99,327	32,776	0	99,327	32,776	0	26,065	3,924	0
महाराष्ट्र	9,70,194	2,65,521	4	9,70,194	2,65,521	4	1,90,750	34,907	2
मणिपुर	299	281	2	299	281	2	22	2	0
मेघालय	552	495	0	552	495	0	96	40	0
मिजोरम	272	196	0	272	196	0	8	8	0
नागालैंड	92	69	0	92	69	0	6	3	0
ओडिशा	44,211	10,436	0	44,211	10,436	0	18,921	2,936	0
पुदुचेरी	11,253	4,839	0	11,253	4,839	0	1,368	391	0
पंजाब	66,470	22,243	0	66,470	22,243	0	14,679	1,520	0
राजस्थान	87,284	17,255	0	87,284	17,255	0	17,777	1,497	0
सिक्किम	1,340	619	0	1,340	619	0	93	21	0
तमिलनाडु	3,67,980	1,33,972	10	3,67,980	1,33,972	10	39,984	9,269	1
तेलंगाना	1,47,667	53,981	0	1,47,667	53,981	0	40,166	5,261	0
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	10,923	3,069	0	10,923	3,069	0	637	63	0
त्रिपुरा	1,635	437	0	1,635	437	0	393	66	0
उत्तर प्रदेश	3,01,996	74,245	1	3,01,996	74,245	1	55,273	8,149	0
उत्तराखंड	84,892	23,192	0	84,892	23,192	0	10,652	1,421	0
पश्चिम बंगाल	97,820	43,625	1	97,820	43,625	1	19,968	3,469	0

(ii) पीएमकेवीवाई:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नामांकित			प्रशिक्षित			प्रमाणित		
	पुरूष	महिला	ट्रांसजेंडर	पुरूष	महिला	ट्रांसजेंडर	पुरूष	महिला	ट्रांसजेंडर
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2,006	1,091	0	1,890	957	0	1,433	773	0
आंध्र प्रदेश	67,356	55,490	2	53,153	43,787	1	35,633	31,873	1
अरुणाचल प्रदेश	10,192	17,662	0	9,134	14,822	0	8,117	13,461	3
असम	63,389	1,39,641	3	47,879	1,12,735	4	41,680	78,592	6
बिहार	95,128	89,852	0	1,00,881	89,833	0	68,251	63,877	0
चंडीगढ़	757	2,115	0	783	1,891	0	656	1,474	0
छत्तीसगढ	16,963	23,822	1	16,781	22,722	0	11,151	15,642	1
दिल्ली	24,334	26,299	1	23,507	24,944	1	17,152	19,369	1
गोवा	374	660	0	571	640	0	426	493	0
गुजरात	54,726	53,527	0	49,394	53,985	0	33,588	38,743	1
हरियाणा	92,013	73,883	1	76,757	63,566	1	53,409	47,238	1
हिमाचल प्रदेश	22,881	25,695	0	18,737	22,334	0	14,167	17,733	0
जम्मू और कश्मीर	65,619	1,13,251	0	53,695	97,442	1	39,290	79,893	1
झारखंड	26,446	34,294	0	34,068	46,542	0	20,877	33,712	0
कर्नाटक	76,285	73,083	0	63,630	60,062	0	47,396	41,240	0
केरल	22,795	22,599	0	19,621	19,611	0	13,340	13,960	0
लद्दाख	617	1,705	0	459	1,275	0	241	815	0
लक्षद्वीप	74	46	0	170	70	0	46	6	0
मध्य प्रदेश	2,00,292	2,46,749	1	1,75,185	2,18,582	0	1,16,459	1,53,209	0
महाराष्ट्र	1,18,206	92,097	3	98,666	76,719	4	71,268	53,578	3
मणिपुर	10,986	26,423	15	9,177	23,537	12	5,912	18,061	10
मेघालय	8,283	12,567	0	7,145	10,358	0	5,130	6,922	0
मिजोरम	7,477	11,852	0	6,629	11,458	0	4,188	7,335	0
नागालैंड	11,042	12,845	0	9,668	9,688	0	6,242	6,563	0
ओडिशा	45,128	44,181	1	38,741	36,711	1	24,822	25,574	1
पुदुचेरी	2,485	7,108	1	2,214	6,102	1	1,588	4,615	1
पंजाब	84,695	1,11,994	1	72,540	95,568	1	55,798	76,766	1
राजस्थान	2,35,388	1,72,576	0	2,07,116	1,55,939	0	1,69,561	1,29,364	0
सिक्किम	3,513	5,042	0	3,058	4,371	0	1,456	2,135	0
तमिलनाडु	61,638	1,35,733	5	55,730	1,16,001	3	38,989	91,383	2
तेलंगाना	39,691	38,962	0	34,553	33,176	0	25,307	24,341	0
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	699	1,401	0	705	1,415	0	501	1,092	0
त्रिपुरा	13,559	24,993	0	10,519	19,640	0	8,830	15,211	0
उत्तर प्रदेश	3,63,230	3,88,822	3	3,15,866	3,53,646	2	2,26,590	2,71,208	0
उत्तराखंड	30,999	42,678	0	27,567	37,142	0	19,943	26,048	0
पश्चिम बंगाल	49,958	56,258	1	50,507	60,662	1	32,885	41,665	1

(iii) **जेएसएस**:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नामांकित			प्रशिक्षित			प्रमाणित		
	पुरूष	महिला	ट्रांसजेंडर	पुरूष	महिला	ट्रांसजेंडर	पुरूष	महिला	ट्रांसजेंडर
अंडमान और निकोबार	1,759	6,538	-	1,694	6,403	-	1,694	6,396	-
आंध्र प्रदेश	11,482	74,696	112	11,378	73,016	112	11,309	72,148	101
असम	11,489	64,834	14	11,346	63,065	14	11,255	62,010	13
बिहार	42,769	2,11,676	45	41,912	2,04,285	45	40,100	1,96,586	43
चंडीगढ़	3,938	9,954	8	3,719	9,279	8	3,591	9,092	7
छत्तीसगढ	33,044	1,30,455	66	32,333	1,26,165	66	31,628	1,24,046	66
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2,241	15,284	4	2,241	15,191	4	2,041	14,875	4
दिल्ली	8,170	36,293	40	7,633	34,983	40	7,506	34,419	37
गोवा	1,137	12,955	1	1,110	12,655	1	1,062	12,495	1
गुजरात	16,222	1,16,748	48	16,123	1,13,780	48	15,789	1,12,961	48
हरियाणा	10,703	45,927	6	10,553	44,821	6	10,481	42,757	5
हिमाचल प्रदेश	26,122	74,212	10	25,030	70,902	10	24,733	69,926	10
जम्मू और कश्मीर	4,520	11,164	10	4,303	10,840	10	3,925	9,587	8
झारखंड	16,510	1,05,655	22	15,574	98,402	22	15,435	97,533	22
कर्नाटक	21,855	1,35,446	34	21,397	1,31,251	34	21,300	1,29,769	34
केरल	16,458	1,12,473	46	16,121	1,09,196	46	15,945	1,07,721	46
लद्दाख	252	1,388	-	234	1,295	-	59	658	-
लक्षद्वीप	407	4,934	2	395	4,780	2	394	4,701	2
मध्य प्रदेश	59,471	3,41,242	57	58,667	3,33,574	57	57,481	3,27,296	52
महाराष्ट्र	51,232	2,47,395	145	50,752	2,42,158	145	48,982	2,35,597	139
मणिपुर	18,768	34,194	12	18,191	32,867	12	16,141	30,543	11
मेघालय	1,728	5,674	-	1,683	5,316	-	1,683	5,296	-
मिजोरम	3,371	5,357	-	2,722	4,335	-	2,698	4,285	-
नागालैंड	5,021	9,176	5	4,936	8,861	5	4,350	7,635	5
ओडिशा	67,677	2,80,336	101	65,973	2,70,506	98	64,730	2,66,359	96
पंजाब	2,425	22,999	4	2,408	21,899	4	2,404	21,808	4
राजस्थान	21,832	83,941	5	21,191	81,127	5	20,933	80,188	5
तमिलनाडु	16,361	96,255	28	16,275	93,548	28	16,006	92,095	26
तेलंगाना	9,831	73,475	34	9,831	73,475	34	9,561	69,680	31
त्रिपुरा	6,003	17,016	6	5,894	16,132	6	5,875	16,024	6
उत्तर प्रदेश	1,14,485	5,62,745	118	1,11,333	5,46,705	118	1,10,122	5,39,587	116
उत्तराखंड	14,846	88,110	23	14,366	86,169	23	14,065	85,296	23
पश्चिम बंगाल	19,504	86,516	31	19045	82916	31	18,848	81,849	29

(iv) **सीटीएस/आईटीआई**:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नामांकित			प्रशिक्षित/आकलित			प्रमाणित		
	पुरूष	महिला	ट्रांसजेंडर	पुरूष	महिला	ट्रांसजेंडर	पुरूष	महिला	ट्रांसजेंडर
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2177	952	0	1354	585	0	1236	547	0
आंध्र प्रदेश	239562	11388	0	170184	6338	0	145280	5211	0
अरुणाचल प्रदेश	2403	867	0	1558	605	0	1325	556	0
असम	16995	5359	0	10584	3115	0	9734	2875	0
बिहार	520701	39196	4	389199	26777	1	307431	21660	0
चंडीगढ़	2539	2434	0	1515	1564	0	1402	1492	0
छतीसगढ	81433	32135	1	49477	15706	0	43938	13892	0
दिल्ली	33141	15520	0	20321	9053	0	18542	8531	0
गोवा	8788	2238	0	5766	1283	0	5181	1215	0
गुजरात	346794	87138	7	202244	39863	5	171478	33418	4
हरियाणा	200888	53191	0	128612	31611	0	108808	29247	0
हिमाचल प्रदेश	78854	23313	1	60380	16444	1	54915	15751	1
जम्मू और कश्मीर	25802	17165	2	15168	10279	1	13390	9221	0
झारखंड	182510	11521	4	127719	6535	2	99701	5280	2
कर्नाटक	338534	15782	0	224860	9317	0	177659	6881	0
केरल	131201	32806	0	93093	21643	0	87231	20642	0
लद्दाख	731	930	0	385	562	0	340	503	0
लक्षद्वीप	914	674	0	656	457	0	550	365	0
मध्य प्रदेश	302564	52435	4	206347	29685	1	151803	20414	1
महाराष्ट्र	503774	105815	0	345647	66706	0	295356	58561	0
मणिपुर	2171	1030	2	1246	510	0	841	371	0
मेघालय	2302	1650	0	1527	912	0	1377	842	0
मिजोरम	1124	450	0	642	249	0	594	215	0
नागालैंड	1039	357	0	647	185	0	588	173	0
ओडिशा	248468	44940	2	174756	25574	0	131782	16959	0
पुदुचेरी	2948	673	0	1780	351	0	1479	336	0
पंजाब	147837	60755	0	93236	36798	0	72127	31890	0
राजस्थान	437338	46266	4	318217	29401	3	221253	21267	2
सिक्किम	1066	635	0	646	379	0	609	368	0
तमिलनाडु	154028	25254	4	88650	13141	2	75559	11871	2
तेलंगाना	144851	12426	0	97563	6380	0	74473	5294	0
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2806	874	0	1782	396	0	1602	374	0
त्रिपुरा	8085	3394	0	4008	1672	0	3286	1459	0
उत्तर प्रदेश	1367169	211590	0	931039	122016	0	626852	96090	0
उत्तराखंड	42932	8479	0	29344	4939	0	22743	3971	0
पश्चिम बंगाल	167558	26107	3	119320	16176	2	107384	14578	2

*****